[श्री योगेन्द्र शर्मा]

या नहीं यह तो तभी पता चलेगा जब सदन इस पर विचार करेगा...

श्री मधु लिमये : वह प्रैस नहीं करते हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : तब मामला खत्म है।

SHRI S. S. KOTHARI : In view of the fact that Mr. Madhu Limaye has pointed out that it is the convention of the House that we do not oppose the introduction of Private Members' Bills, I withdraw my objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 1956."

The motion was adopted.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : I introduce the Bill.

16.11 hrs.

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Sections 2, 3, etc.)

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954."

The motion was adopted.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : I introduce the Bill.

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated 24-4-1970.

16.12 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL— *contd.*

(Omission of Article 314)

by Shri Madhu Limaye

MR. DEPUTY-SPEAKER : We take up further consideration of the Bill of Shri Madhu Limaye further to amend the Constitution of India. Originally the time allotted was one hour. We have taken four hours and 52 minutes and more Members would like to speak. Shri Raghuvir Singh Shastri may continue his speech.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार की सर्विसिस में यदि किन्हीं लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है तो वे समाप्त होने चाहियें। उसने कहा है कि सभी आदमियों को, सभी श्रेणियों को समान सुविधायें मिलनी चाहिएं, सब के लिए द्वार समान होने चाहियें और किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलने चाहियें और जिन को मिले हुए हैं, उनके समाप्त होने चाहियें। प्रशासनिक सुधार आयोग की शिफारिशों को देखते हुए भी मैं यह समझता हूं कि यह बड़ा आवश्यक है कि भारत सरकार की जो सर्विसिस हैं, उनमें किसी एक खास सर्विस को अगर विशेषाधिकार मिले हुए हैं, तो उनको समाप्त किया जाना चाहिये। भारत सरकार की सर्विस में लगभग 27 लाख आदमी हैं और प्रान्तीय सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुये आदमियों को गिना जाए तो उन की संख्या करीब नब्बे लाख हो जाती है। देश की सरकारी सर्विसिस में लगभग नब्बे लाख लोग हैं। अब 80,90 या 100 आदमियों को जो विशेषाधिकार मिले हुये हैं, वे बड़े अखरते हैं और इसलिये वे समाप्त होने चाहियें।

अब प्रश्न पैदा होता है कि इसके लिये

क्या संविधान को बदलना पड़ेगा ? कुछ लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना नैतिकता नहीं होगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि बदलते हुये समाज में और बदलते हुए युग में यदि संविधान को बदलने की आवश्यकता पड़े तो उसको बदलना भी नैतिकता है और न बदलना अनैतिकता है । इस लिये मैं समझता हूं कि यदि आवश्यकता है और नैतिकता का तकाजा है तो संविधान को भी बदल दिया जाना चाहिये । मैं यह भी समझता हूँ कि यदि आज सरदार पटेल जीवित होते तो वह हम सब का नेतृत्व करते इस बात में और सबसे आगे हो कर कहते कि परिस्थितियां बदल गई हैं और बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये और ये जो विशेषाधिकार इन लोगों को दिये गये हैं, वे समाप्त किये जाने चाहियें ।

संविधान में जब हमने इसकी व्यवस्था की या इसके बारे में आश्वासन दिया तो उसके पीछे भी एक बात थी और वह यह थी कि हमारे जो ब्रिटिश शासक थे उनका एक अनुरोध था, उनका एक आग्रह था जिसे एक प्रकार से कभी-कभी दबाव भी माना जा सकता है और उस अनुरोध या यों कहिये कि उस दबाव में आकर हमने इन 80 या 90 या 100 आदमियों को सरकार में इस प्रकार का दर्जा दिया जिस से यह भान होता है, जिस से ऐसा आभास मिलता है कि वे ब्रिटिश सरकार के आदमी हैं, भारत सरकार के आदमी नहीं हैं । यह जो मनोवैज्ञानिक संस्कार है, यह भी समाप्त होना चाहिये और यह जो भावना है, यह समाप्त होनी चाहिये । उनके मन में भी यह भावना होनी चाहिये कि वे ब्रिटिश सरकार के रखे हुए नहीं हैं, अंग्रेजों के रखे हुये नहीं हैं बल्कि भारतीय शासन या भारतीय सरकार के अधीन जो दूसरे कर्मचारी हैं या सर्विसिस हैं, उनमें और इनमें कोई भेद नहीं है । यदि ये विशेषाधिकार समाप्त नहीं होंगे तो हमेशा उन्हें यह ध्यान रहेगा कि हम ताज के द्वारा रखे हुए हैं, हम ताज के प्रति वफादार है, ताज ने हमारी सुविधाओं को सुरक्षित रखा है ।

27 लाख की तो एक बिरादरी है और अगर सरकारी कर्मचारियों की पूरी बिरादरी को लिया जाए तो वह 80-90 लाख के करीब होती है । इतनी बड़ी बिरादरी में अगर 80, 90 या 100 आदमी जो अलग-थलग हैं वे यह कहें, यह आफर करें कि आज हम जो हमारी समाज में ऊंचपन और नीचपन है, जो ऊबड़ खाबड़ धरातल है, उसको दूर कर रहे हैं, उस को बराबर कर रहे हैं तो भी उचित होगा । ये बहुत बड़ा अन्तर नहीं है जिनको वे मिटायेंगे । बहुत छोटा सा अंतर है और इस लिए उनको अपने आप आफर करना चाहिये और यह कहना चाहिये कि हमारी वजह से अगर कहीं समाज में कोई भेद रहता है तो वह समाप्त होना चाहिये । उनके लिए यह एक शोभा की बात होगी । सौ के करीब जो आई० सी० एस० के आदमी है वे स्वयं आफर करें कि आज हम सुविधाओं को छोड़ते हैं और सरकारी सर्विसिस की जो बिरादरी है, उसमें शमिल होते हैं, दूसरी सेवा करने वालों की जो बिरादरी है, उसमें शामिल होते है तो यह सब से अच्छी बात होगी ।

श्री लिमये ने इस बिल को रखा है । इस को लाने की मंशा यही है कि एक बिरादरी में जो अछूत बचे हुए हैं, वे भी बिरादरी में शामिल हो जायें और जो अलग से एक स्थान उनको मिला हुआ है, उसको समाप्त करके मनोवैज्ञानिक रूप से, क्रियात्मक रूप से सब को समान आधार पर रखा जाए, भारत के सब नागरिक एक समान हैं और भारत सरकार की सेवा में काम करने वाले सब लोगों के साथ एक दृष्टि से व्यवहार होता है, एक दृष्टि से उन के साथ बरताव होता है ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, यह विधेयक

[श्री शिव चन्द्र झा]

1967 में पेश किया गया था। चाहिये तो यह था कि चूंकि इस प्रकार के विधेयक के माध्यम से प्रगति की तरफ कदम बढ़ता है, इसलिए सरकार या तो इस विधेयक को स्वीकार कर लेती और या अपनी तरफ से इस तरह का कोई विधेयक लाती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। हाल ही में यह विधेयक बैलट में आया और इस सदन में उस पर बहस शुरू हुई। इन तीन सालों में देश का वातावरण बहुत बदल गया है। पहले तो सत्तारूढ़ दल का यह घमंड था कि हमारी हस्ती बरकरार है और कोई हमको चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन 1967 के बाद परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। कई राज्यों में सत्तारूढ़ दल की हस्ती को धक्का लगा है वह जानता है कि उसकी नैया डूबने को है और यदि उसने इस प्रगतिशील कदम का समर्थन नहीं किया, तो केन्द्र में भी उसके अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा। इस लिए, जैसा कि अखबारों में आया है, सरकार अपनी गर्दन को बचाने के लिए इस विधेयक का समर्थन करने जा रही है। कहावत है कि बैटर लेट दैन नेवर या देर आयद दुरुस्त आयद। सरकार अब भी इस विधेयक का समर्थन करने के लिए तैयार हो गई है, इस बात की हमें खुशी है। लेकिन हम उसको इस बात के लिए माफ नहीं करेंगे कि उसने इतने दिनों तक इस विधेयक को नजर अन्दाज किया। यदि इस सदन में इस तरह का कोई प्रगतिशील विधेयक आये, तो सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिये और अगर सरकार किसी निजी विधेयक को स्वीकार नहीं करना चाहती है, तो वह अपनी तरफ से एक विधेयक लाये।

मैं आई० सी० एस०—इंडियन सिविल सर्विस—की शुरुआत में नहीं जाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि अंग्रेजी जमाने में राष्ट्रीय नेता कहा करते थे कि यह न सिविल है और न सर्विस है हकीकत यही है कि इंडियन सिविल सर्विस के ये अफ़सरान सिविल नहीं थे, क्योंकि उनको मैन्टेलिटी मिलिटरी या पैरा मिलिटरी होती थी और उनका उद्देश्य सर्विस तो था ही नहीं, बल्कि उनके मनों में इस देश के लोगों पर डामीनेशन करने की भावना थी। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और श्री हरिविष्णु कामत जैसे जिन लोगों को इस बात का अहसास हो जाता था, वे इस सर्विस को छोड़ जाते थे। जहां तक श्री अरबिंद का संबंध है, वह हार्स-राडिंग में कम्पीट न कर सकने की बजह से इस में नहीं आ पाये, लेकिन अगर वह आ भी जाते, तो वह भी इसको छोड़ देते। जैसा कि मैंने कहा है, जिन लोगों को इस सर्विस की वास्तविकता का ज्ञान हो गया, वे इसको छोड़ गए और समाज-सेवा के काम में लग गए।

अंग्रेजी साम्राज्य के जमाने में इस सिविल सर्विस की स्थापना के पीछे दो उद्देश्य थे: एक स्टेबिलिटी और दूसरा कान्टीन्यूइटी। जब अंग्रेज यहां से गए और ट्रांसफ़र आफ़ पावर हुआ तो उस वक्त भी हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसी बात को दृष्टि में रखा और संविधान में अनुच्छेद 314 रख कर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के प्रिविलेज आदि बरकरार रखे। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया आदि जिन एशियाई देशों में इस प्रकार की सर्विस नहीं थी, वहां कई खराबियां पैदा हुई।

लेकिन अब समय बदल गया है, देश की परिस्थिति बदल गई है, जिसके कारण सरकार को मजबूरन कई परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। इसी वजह से उसने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का आदर्श रखा है, हालांकि वह केवल दिखाने के लिए ही है। लेकिन अगर इस सरकार का उस आदर्श में

थोड़ा भी विश्वास है, तो उस के लिए यह लाजिमी है कि वह देश में मौजूद अलग अलग वर्गों के प्रिविलेजिज़ का खात्मा करने की कोशिश करे। पूंजीवादी देशों में भी सामाजिक तफ़र्रकों औ प्रिविलेजिज़ का खात्मा हो रहा है। अमरीका जैसे पूंजीवादी देश में शासन के अधिकारियों आदि के विशेषाधिकारों और विशेष स्थिति को लगभग समाप्त कर दिया गया है। आप किसी भी दफ़्तर में चले जाइये, आपको कोई नहीं रोकेगा। वहां यह भी मालूम नहीं होगा कि अमुक व्यक्ति मैजिस्ट्रेट, गवर्नर या जुडिशरी का आदमी है। यह ठीक है कि वहां रंग-भेद है और एशियन्ज के साथ भेद-भाव बरता जाता है, लेकिन कागज पर "आल आर ईक्वल" के सिद्धान्त को बहुत हद तक निभाने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटेन में भी लार्डशिप और मानार्की होने के बावजूद सब को समान स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है। जब पूंजीवादी देशों में भी ये परिवर्तन हो रहे हैं, तो फिर जो सरकार समाजवाद और सोशलिस्ट पैटर्न का साइनबोर्ड अपने माथे पर लगाये फिरती है, उसके लिए तो इस प्रकार के वर्गीय विशेषाधिकारों को खत्म करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।

हम यह देख रहे हैं कि आई० सी० एस० के बाद अब आइ० ए० एस० में जो लोग आये हैं, उनमें भी विशेषाधिकार और विशेष स्थिति को प्राप्त करने और बनाये रखने की भावना है। इस विधेयक के पीछे दर्शन केवल यह नहीं है कि सिविल सर्विस के प्रिविलेजिज का खात्मा किया जाये। वे तो खत्म किये जाने चाहिये ही और उस बात का हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे अफ़सरों में जो हाकिमाना दिमाग़ है, जो डामीनेशन की भावना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर बड़े-बड़े अफ़सर आम जनता के साथ जो डिसक्रिमिनेशन करते हैं, उसको भी खत्म करने की जरूरत है।

यदि सरकार को इस विधेयक की भावना और आदर्श के साथ कुछ हमदर्दी है, तो वह अपने अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी करे कि जो कोई नागरिक कोई दरख्वास्त ले कर उनसे मिलने के लिए आता है, तो वे ध्यान और आदर से उसकी बात सुनें। आज यह स्थिति नहीं है। आज तो बी० डी० ओ० भी अपने आप को लाट साहिब समझता है। धन की असमानता और केन्द्रीयकरण को तो दूर करना ही चाहिये, लेकिन उसके साथ-साथ सामाजिक असमानतों को भी जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिये।

अगर हम संविधान की किसी व्यवस्था के कारण इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हम को उस में संशोधन करना चाहिये। इस दृष्टि से आज हमारा यह फ़र्ज हो जाता है कि हम संविधान के अनुच्छेद 314 को डिलीट कर दें, ताकि कागज़ पर बराबरी की भावना बढ़े। इससे लोअर रैंक्स में भी, गांवों और ब्लाक के छोटे-छोटे अधिकारियों में भी समाजवाद और बराबरी की भावना आयेगी।

केवल इस विधेयक को स्वीकार करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो लांग-रेंज दर्शन है, सरकार उसको भी स्वीकार करे और यह आश्वासन दे कि वह एक सर्कुलर जारी करेगी कि अधिकारी आम जनता के प्रति बराबरी की भावना रखें और उनकी ग्रीवेंसिज़ को दूर करने की कोशिश करें। ऐसा करने से ही यह प्रमाणित हो सकेगा कि यह सरकार समाजवाद या सोशलिस्टिक पैटर्न में विश्वास रखती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secundrabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset I would like to say that though I welcome the move made by my hon. friend, Shri Madhu Limaye, I can give him only qualified support.

[Shri Bakar Ali Mirza]

I entirely agree with what has been said about the Indian Civil Service and the way in which it has been functioning. The Indian Civil Service was created by the British Government when they realised in 1857 that mere lathi and guns will not solve this problem but a state has to be created in which the British social order is respected in this country. On the ne side, they had Macaulay with his educaoional programme ; on the other, they had thte service which they called the Indian Civil Service, in whicb the brilliant students were selected and they were trained in England and steeped in British culture and British view of things in general. They were sent mostly either to Oxford or Cambridge which are the biggest factories in the world to manufacture the best snobs in the noblest sense of the word. With this additional snobbery and the great authority and prestige of the British Government, the Indian Civil Service represented in India some sort of superior humun being, superior Indian, not equal to the Englishmen but a sort of brown Englishmen in this country. That was the view of the British Government. They were paid so well and they were given such other advantages that they were also fairly honest in dealing with the people

Therefore, this service was created by the British Government for a special purpose and that special purpose they served very well. In crushing the freedom movement, in doing everything possible so that freedom is delayed as long as possible, they left no stone unturned in that.

But that is only one aspect of the question that the Indian Civil Service is not a desirable institution which should be tolerated. That is one part of the question and not the main thing. In the Bill you want to delete Article 314 relating to the agreement we have come to with the Indian Civil Service. Now, by an Act that was passed in 1935, Secretaries of State Service were protected in this manner. I want to assert that this is not a privilege. There were certain conditions of service which were guaranteed and they were offered by Government ; they were not asked by the Indian Civil Service but were offered by the Government. A note has been circulated by the Home Minister :

"The Government of India are naturally and rightly most anxious and His Majesty's Government share their anxiety—that the administration shall not be weakened by the loss of experienced officers."

So, Sir, Government required them on their terms. I know the whole thing was managed by Britishers. They wanted to protect the loyal servants, but at the same time they had the capacity to make their ideas originate from the victim itself. It is they who partitioned the country but the idea was supposed to emerge from Mr. Jinnah or X, Y or Z. That is why the Government of India offered them certain conditions, and if they did not accept those conditions they were to retire. So, when you make an offer and the other party accepts it, it is a contract and it is not a privilege. Privileges are really enjoyed by you, me and the princes and not by the Indian Civil Service. Article 314 deals with conditions of service of Indian Civil Service. Article 311 deals with conditions of service of IAS and so on and so forth. This is a question involving amendment of the Constitution and the Home Minister wanted that we deal with that aspect exhaustively. Let me make my point clear. It is not a question of privilege. I hold that there should not be any inequality and privilege in this country. Even Jackson of the United States said that there should be no inequality and no special privileges. But, Sir, the abolition of privileges and so on should begin with ourselves and not with others. It is very easy to take away the privilege of others with whom we have no concern. Is it not a fact ? Take, for example, the princes and the Members of Parliament. The Members of Parliament not only enjoy privileges but also there is no check on the abuse of those privileges. The princes have certain privileges but they cannot over-step them. Here you cannot criticise somebody who is not present, but everyday there is criticism. What is the check ? Not only that you have got the privileges but also you can extend the same as long and as much as you like. A year back we increased our salaries, telephone facilities, etc. We increased our own privileges. Therefore, I maintain that privileges and inequalities should not be there and we should start with ourselves first.

Secondly, there is the question of some pledge, some guarantee which you have given

and which you cannot really discard because the conditions of India have changed. In what way have the conditions of India changed ? In what way have the ICS officers come in the way of any socialist measures ? You do not take any measure and you want to blame somebody or the other. That will not do.

One reason why we are very keen about this is that we have not succeeded in bringing about socialism When Napoleon was retreating from Moscow, he built a dome with gold so that everybody was talking about the gold dome and forgot about his defeat.

You have to honour the word that you had given. We are great believers in Gandhiji. Gandhiji said that after freedom his main task would be, firstly, to purify the politics of the country ; secondly, to organise the masses to insist and press that all the pledges that we had given during the time of our slavery were honoured and fulfilled and, thirdly, to organise the youth so that their restlessness and ideology got some outlet.

Though the purpose and intention are very good, I do not think we will be doing credit to our country by changing our word so easily and so often

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Hanumanthaiya.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) . Sir I have a submission regarding this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can raise a point of order.

SHRI S. M BANERJEE : I have no point of order : it is a submission regarding time for this Bill. It is a really very important Bill. Some of us who did not understand the implications of the Bill at the initial stage have now fully understood them. We want to participate in the debate. The Chairman of the Administrative Reforms Commission is speaking on this Bill. He may give us some clues. Therefore, I move :

> 'That the time for this Bill be extended by two hours."

This is the motion for my side. If somebody wants to object to it, let him object.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : I support it.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : I beg to oppose what Shri S. M. Banerjee has stated In view of the present political climate my Bill was considered as important by the sub-committee of the Private Members' Bills and Resolutions Committee and has been upgraded to category A. I have been sitting here for the last three days.

SHRI S. M. BANERJEE : I am here for the last three months.

SHRI P. K. DEO : Here "three days" means a month and a half On this Bill for which only one hour was allotted, more than five hours have been consumed All aspects of Shri Madhu Limaye's Bill have already been dealt with. Therefore I bring forward a closure motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The first motion is before the House.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : I want to suggest a *via media*. As Shri Banerjee has pointed out, it is an important Bill and many Members want to participate in the debate on this. I understand, the Government is supporting the Bill ; probably, they have even issued a whip to their Members to support the Bill. I do not know but that is what I understand. We would require a two-thirds majority before the Bill is passed. If time is extended for this Bill, other Private Members' Bill will be debarred which is not proper. Therefore, I suggest that since Government is supporting the Bill, let Government take over this Bill, give time from their own time and fix a date for this. On the 28th we are having the elections to the Estimates Committee. Probably many Members, more than the required number, would be present that day. Let Government provide one hour or two hours, whatever we fix now, from their own time and let this Bill be voted on that day. Today we may continue with other Private Members' Bill.

SHRI S. M. BANERJEE : I withdraw my earlier suggestion in favour of Shri Dwivedy's suggestion.

SHRI S. KANDAPPAN : I strongly feel that since Shri Deo's Bill is also a very important and topical one, we should discuss that Bill also. Government has already made up its mind, as has appeared in the papers, that they are going to support this Bill.

As Mr. Dwivedy suggested, it can be made a Government Bill, they can bring it and there will not be any difficulty in getting it passed. On a previous occasion also, Shri Nath Pai's, Bill was taken up by the Government. Then, we can take up Shri P. K. Deo's Bill today.

SHRI P. K. DEO : There should not be any bad precedent created because of absence of Members today and the Constitution Amendment Bill not being passed. To avail of the opportunity of Members being present for the Estimates Committee elections on the 28th for the purpose of passing the Constitution Amendment Bill on that day is a very bad precedent. This is very wrong. I oppose this move.

SHRI NAMBIAR : Sir, my only submission is that if we postpone it to any other day, other than a Friday—on 28th, it is not a Friday—then the time has to be taken from the Government quota. Therefore, I want a firm commitment from the Government that they will agree to do that.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : The Government has no objection. In fact, the Government supports the suggestion made by Mr. Dwivedy and Mr. Nambiar. Being an important matter, a good discussion is necessary. Although this Constitution Amendment Bill is only one-line Bill, a large volume of matter is contained in it, the consequences have to be explained and all that. I myself wanted to speak on the Bill about the legal, constitutional and other aspects. Therefore, I support the suggestion made by Mr. Dwivedy.

SHRI P. K. DEO : Why should it be on the 28th ?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Let me make a motion and let it be accepted by the House. I want Rule 30 (1) and other relevant rules in relation to the Constitution Amendment Bill of Shri Madhu Limaye to be suspended and that the debate on the consideration of Shri Madhu Limaye's Bill be now adjourned and be taken up at 6.00 P. M. on 28th April, 1970.

28

SHRI P. K. DEO : I oppose it. Why should it be on the 28th ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): You make it from 6.00 P. M. to 6.30 P. M.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : We will take it up at 6.00 P. M.

This is my motion.

SHRI S. M. BANERJEE : 28th April is all right. I only want it should be from 6.00 P. M. to 7.00 P. M.

SHRI RAGHU RAMAIAH : That is all right.

SHRI P. K. DEO : I fully appreciate the gesture of the Government to accommodate Shri Madhu Limaye's Bill. Why should it be on the 28th ? That is what I object to. From what Shri Dwivedy has said, the motive is *mala fide*. Today, there is no strength in the House and there is no chance of the Bill being passed. Now, because the Members will be present on the 28th for the Estimates Committe elections, they want to avail of that opportunity so that the Bill is taken up on that day to get it passed. I object to this. Surely, the law of jungle is not prevailing here. It is a bad precedent ; it is a wrong thing. So, I oppose the motion of Shri Dwivedy.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Since Shri P. K. Deo has mentioned certain things, I would say, it is with the best of intentions to accommodate Shri P. K. Deo's Bill. Everybody knows that the Government has accepted the Bill and that the Bill is going to be passed. It is in order to accommodate him that we are suggesting this. He should take it in that light.

SHRI P. K. DEO : I oppose 28th.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Rule 109 says :

"At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : श्री सुरेन्द्र द्विवेदी ने ठीक सुझाव दिया है। क्योंकि यह प्राइवेट मेम्बर्ज बिजनेस है, इसलिए इसमें रूल को सस्पेण्ड करना पड़ेगा। नाथपाई के बिल के समय भी ऐसा ही किया गया था, पहले रूल को सस्पेण्ड करवाया था, उसके बाद निश्चय किया गया था। इसलिये पहले रूल को सस्पेण्ड करने का मोशन पास हो, उसके बाद इसको लिया जाय।

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : The relevant rule is 30 (1).

MR. DEPUTY-SPEAKER : Rule 30 (1) says :

"When on a motion being carried the debate on a private members's Bill or resolution is adjourned to the next day ....."

That does not apply.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Sir, I beg to move :

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill (*Omission of Article 314*) by Shri Madhu Limaye be adjourned to Tuesday, the 28th April, 1970 at 6 p. m."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill (*Omission of Article 314*) by Shri Madhu Limaye be adjourned to Tuesday, the 28th April, 1970 at 6 p.m."

The motion was adopted.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY ; Sir, I beg to move :

"That rule 30 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the debate on the Constitution (Amendment) Bill by Shri Madhu Limaya which has been adjourned today to Tuesday, the 28th April, 1970 be suspended."

MR. DEPUTY SPEKAER : The question is :

"That rule 30 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the debate on the Constitution (Amendment) Bill by Shri Madhu Limaya which has been adjourned to-day to Tuesday, the 28th April, 1970 be suspended."

The motion was adopted.

SHRI P. K. DEO : Sir, I oppose it.

SHRI S. M. BANERJEE : I support it.

16.44 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 164)
by Shri P. K. Deo

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up the Bill of Mr. P. K. Deo.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : I beg to move :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

Mr. Deputy Speaker, Sir, the Committee on Private Members Bills and Resolutions has up-graded this Bill as Category A having realised its importance and implications in the context of the recent developments in the country. This Bill is so simple, so innocuous, so non-controversial and at the same time so timely and important for the proper functioning of democracy that not much pleading is necessary for the passing of this Bill. This Bill provides to amend Article 164 of the Constitution which empowers Governors to appoint Chief Ministers and other Ministers in the State. Article 164 of the Constitution says, and I quote :

"The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief